www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 151 | जौनपुर गुरूवार, 15 जनवरी 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

रायगढ़ में युवा कांग्रेस सम्मेलन और सम्मान समारोह सफलतापूर्वक संपन्न

रायगढ़, (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला युवा कांग्रेस के तत्वावधान में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन एवं सम्मान समारोह क्षेत्रीय विधायक के गृह ग्राम में मंगलवार को संपन्न हुआ।कार्यक्रम का आयोजन जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष उष्मान बेग के नेतृत्व में तथा युवा कांग्रेस परिवार जिला रायगढ़ के सौजन्य से किया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ स्व. चनेशराम राठिया, महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर सहित अन्य महापुरुषों के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन कर किया गया। सम्मेलन में जिले भर से बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, युवाओं को राजनीति एवं समाज सेवा से जोड़ने तथा आगामी चुनावी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस संगठन की रीढ़ है और युवाओं की सक्रिय भागीदारी से ही लोकतंत्र को मजबूती मिलती है।इस अवसर पर संगठन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह से उपस्थित कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। कार्यकर्ताओं ने संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए ।

दिल्ली सरकार 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनता को करेगी समर्पित

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली सरकार विस्तार के 5वें चरण के तहत 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली की जनता को समर्पित करेगी, जिससे राजधानी दिल्ली में वार्ड और मोहल्ला स्तर पर प्राइमरी हेल्थकेयर सेवाओं को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। इस बढ़ोतरी के साथ राजधानी दिल्ली लॉन्ग–टर्म प्राइमरी हेल्थकेयर रोडमैप के तहत तय किए गए 1100 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना की दिशा में लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। दिल्ली में अभी 238 आयुष्मान आरोग्य मंदिर काम कर रहे हैं। बुधवार को 81 नए आरोग्य मंदिरों के उद्घाटन के बाद नेशनल कैपिटल रीजन में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की कुल संख्या बढ़कर 319 हो जाएगी।आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली सरकार के हर घर के पास मुफ्त, सुलभ और सम्मानजनक प्राइमरी हेल्थकेयर देने के मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। यह पहल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कुशल नेतृत्व में प्रत्येक नागरिकों के लिए हेल्थकेयर के राष्ट्रीय विजन के तहत लागू की जा रही है। दिल्ली के हर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में डॉक्टर्स, कंसल्टेशन, जरूरी दवाएं और डायग्नोस्टिक टेस्ट के साथ–साथ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर की स्क्रीनिंग, मां और बच्चे की हेल्थकेयर, मुफ्त टीकाकरण है।

राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री ने वीरों के साहस और बलिदान को किया सलाम

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ष्पूर्व सैनिक दिवस पर, मैं हमारे पूर्व सैनिकों की बहादुरी, समर्पण और बलिदान को सलाम करती हूं। उनका अटूट साहस हर भारतीय को प्रेरित करता रहता है। पूर्व सैनिक दिवस और सशस्त्र सेना झंडा दिवस जैसे मौके न सिर्फ हमारे बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के अवसर हैं, बल्कि उन्हें सार्थक समर्थन देने के भी मौके हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे पूर्व सैनिक राष्ट्र के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे।ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को सशस्त्र सेना वेटरन्स डे पर पूर्व सैनिकों, सेवारत कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दीं, और सीमाओं की रक्षा करने और भारत की भावना को बनाए रखने के लिए उनके बलिदानों की सराहना की। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर संदेश साझा करते हुए कहा कि वह देश के पूर्व सैनिकों और वर्तमान में सेवा दे रहे सभी सैन्यकर्मियों के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि इन वीरों का जीवन साहस, सम्मान और स्वयं से पहले राष्ट्र सेवा के संकल्प को समर्पित है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि संकल्प और अटूट विश्वास के साथ दिए गए उनके बलिदान हमारी सीमाओं की मजबूत ढाल हैं। ये बलिदान न केवल हमारे गणतंत्र की आत्मा की रक्षा करते हैं, बल्कि भारत की अटूट और शाश्वत भावना के सजीव प्रतीक भी हैं। रक्षा मंत्री ने आगे कहा, राष्ट्र की अपने सैनिकों के प्रति कृतज्ञता शाश्वत है, और पूर्व सैनिकों, सेवारत कर्मियों और उनके परिवारों की गरिमा, कल्याण और भलाई के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पूर्ण, अटूट और दृढ़ रहेगी। सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस स्वर्गीय फील्ड मार्शल के.एम. करिअप्पा की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो 1953 में इसी दिन सेवानिवृत्त हुए थे। यह दिन भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा देने वाले बहादुर सैनिकों को सम्मानित करने और पहचानने के लिए समर्पित है। इस दिन को मनाने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

सीएम योगी से मुलाकात कर गदगद हुए बादशाह

मुंबई, (एजेंसी)। रैपर और गीतकार बादशाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बादशाह ने मुलाकात को बेहद खास बताया। इसके साथ ही उन्होंने सीएम योगी की प्रशंसा भी की। इंस्टाग्राम अकाउंट पर किए पोस्ट में उन्होंने सीएम योगी के व्यक्तित्व की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मुलाकात से उन्हें एक अजीब–सी गहरी शांति महसूस हुई। बादशाह ने लिखा, "योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर आज एक शांति महसूस हुई। उनके चेहरे पर एक अलग ही रोशनी है, वो तेज जो शब्दों से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता से आता है।" उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बेहद शांत और सहज स्वभाव का बताया। पोस्ट में बादशाह ने आगे कहा कि योगी जी में जानवरों के प्रति गहरा प्रेम, इंसानों के लिए करुणा और जीवन का एकमात्र उद्देश्य देश की सेवा, धर्म की रक्षा और लोगों के लिए पूरा समर्पण दिखाई दिया। उन्होंने लिखा, "जो लोग उन्हें दूर से देखते हैं, वो बहुत कुछ नहीं समझ पाते। लेकिन पास से मिलने पर पता चलता है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत सत्ता नहीं, बल्कि उनकी संवेदना है। बादशाह इस साल गोरखपुर महोत्सव में शिरकत किए थे। 13 जनवरी को बादशाह का लाइव कॉन्सर्ट रहा। बादशाह के अलावा, मुख्य आकर्षण वरुण जैन, भोजपुरी स्टार पवन सिंह, मैथिली ठाकुर समेत अन्य सितारे शामिल हुए। गोरखपुर महोत्सव का उद्घाटन पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया। गोरखपुर महोत्सव उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर का सबसे बड़ा वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है, जो गोरखपुर की विरासत, आधुनिकता और पर्यटन को बढ़ावा देता है, जहां लोग मनोरंजन, खरीदारी और सांस्कृतिक अनुभव का आनंद उठाते हैं। यह हर साल जनवरी में आयोजित होता है और इस बार 2026 में 11 जनवरी से 17 जनवरी तक चंपा देवी पार्क (रामगढ़ ताल के किनारे) में चल रहा है।

ऑपरेशन पवन में शामिल रहे शांति सैनिकों के योगदान को मान्यता : राजनाथ सिंह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। 'ऑपरेशन पवन' में भारतीय सेनाओं ने अद्भुत साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। कई सैनिकों ने कर्तव्य की राह पर चलते हुए वीरगति प्राप्त की। उनका साहस और बलिदान हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा होनी ही चाहिए। बुधवार को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात कही। भारतीय सेना के कई वीर जवानों ने वर्ष 1987 से 1990 के बीच श्रीलंका में शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सद्भाव बनाए रखने के लिए चलाए गए ऑपरेशन पवन में सर्वोच्च बलिदान दिया था। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ऑपरेशन पवन में भाग लेने वाले शांति सैनिकों के योगदान को न केवल खुले मन से स्वीकार कर रही है, बल्कि उनके योगदान को हर स्तर पर मान्यता देने की प्रक्रिया भी चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब 2015 में अपनी श्रीलंका यात्रा पर गए थे, तो उन्होंने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स मेमोरियल पर अपनी तरफ से भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। अब हम नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर भी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के शांति सैनिकों के योगदान को पहचान प्रदान कर रहे हैं और उन्हें पूरा सम्मान भी दे रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, मैं आज से लगभग 40 साल पहले इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के रूप में श्रीलंका में शांति स्थापना के लिए चलाए गए सैन्य अभियान में भाग लेने वाले सभी पूर्व सैनिकों का भी स्मरण करना चाहता हूं।

प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली में 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रमंडल देशों के लोकसभा अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन (सीएसपीओसी) का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे और इसमें विश्व के विभिन्न हिस्सों से 42 राष्ट्रमंडल देशों व 4 अर्ध–स्वायत्त संसदों के 61 लोकसभा अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से बुधवार को जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को सुबह 10:30 बजे सीएसपीओसी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे सभा को संबोधित भी करेंगे। पीएमओ के अनुसार, सम्मेलन में समकालीन संसदीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचार–विमर्श किया जाएगा, जिसमें मजबूत लोकतांत्रिक संस्थानों को बनाए रखने में स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों की भूमिका शामिल है। यह आयोजन कॉमनवेल्थ के भीतर संसदीय संवाद और लोकतांत्रिक सहयोग के केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। चर्चाएं संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने पर केंद्रित होंगी, ऐसे समय में जब दुनिया भर की विधायिकाएं तेजी से राजनीतिक, तकनीकी और सामाजिक परिवर्तनों से गुजर रही हैं। पीएमओ ने जानकारी दी कि सम्मेलन के मुख्य विषयों में संसदीय कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, सांसदों पर सोशल मीडिया का प्रभाव, संसद की सार्वजनिक समझ को बढ़ाने के लिए अभिनव कार्यनीतियां और मतदान से परे नागरिक भागीदारी आदि शामिल हैं। इसके अलावा, यह सम्मेलन स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों को विधायी प्रक्रियाओं, संसदीय नैतिकता और संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों का आदान–प्रदान करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा।

यूपी में 1000 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने का है लक्ष्य

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी तेजी से विकसित होती अवसंरचना के कारण वैश्विक कंपनियों को दीर्घकालिक निवेश के लिए अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उद्योग जगत के विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में यूपी वैश्विक कंपनियों का एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। इसी कड़ी में प्रदेश में 1000 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इससे पांच लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर वह जगह होती है जहां कोई बड़ी विदेशी कंपनी अपने महत्वपूर्ण काम खुद के कर्मचारियों से करवाती है, न कि किसी बाहरी वेंडर से। उप्र जीसीसी नीति 2024 के माध्यम से योगी सरकार ने जिस नीतिगत स्पष्टता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को अपनाया है उससे वैश्विक कंपनियों की सबसे बड़ी चिंता दूर हुई है। इनमें नियमों की अनिश्चितता और प्रक्रियाओं में देरी सबसे प्रमुख थी। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने स्पष्ट ढांचा तैयार किया है जिससे निवेशकों को शुरुआत से ही नियम शर्तें और दायित्व समझ में आ सकें। इससे भरोसे का वातावरण बना है निर्णय लेने की गति तेज हुई है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में इस समय लगभग 90 जीसीसी हैं। भूमि आधारित प्रोत्साहन, निवेश की शुरुआती लागत को घटाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सरकार की सोच है कि जब निवेशक को शुरुआती चरण में संरचनात्मक सहयोग मिलेगा तो वह लंबे समय तक प्रदेश से जुड़ा रहेगा। यही कारण है कि अस्थायी ऑफिस या किराए की व्यवस्था के स्थान पर स्थायी औद्योगिक ढांचे को प्राथमिकता दी जा रही है। यह मॉडल प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को मजबूत और स्थिर बनाने में अहम है। राज्य सरकार का जोर केवल निवेश आकर्षित करने तक सीमित नहीं है, इसके समयबद्ध क्रियान्वयन पर भी है। इसके लिए जवाबदेही तय की गई है जिससे परियोजनाएं तय समय में पूरी हो सकें। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के जरिये प्रदेश में हाई वैल्यू रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, डाटा और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव मिल रहा है। इससे न केवल प्रदेश की मानव संसाधन क्षमता सुदृढ़ होगी बल्कि प्रतिभा पलायन पर भी प्रभावी रूप से नियंत्रण होगा। विशेष रूप से कम विकसित क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित कर सरकार क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। जब वैश्विक कंपनियां इन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगी तो स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

अलका ठाकुर के समक्ष पेश होने के समय में बदलाव की मांग नहीं की : भगवंत मान

पंजाब, (एजेंसी)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि उन्होंने अकाल तख्त के समक्ष पेश होने के समय में किसी प्रकार के बदलाव की मांग नहीं की है और 15 जनवरी को सुबह 10 बजे के मूल कार्यक्रम के अनुसार ही उपस्थित होने के लिए तैयार हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने कहा, मैंने भारत के राष्ट्रपति कार्यालय को भी उस दिन (अमृतसर के जीएनडीयू विश्वविद्यालय में) उनके कार्यक्रम में शामिल होने में अपनी असमर्थता के बारे में सूचित कर दिया है, क्योंकि 15 जनवरी पूरी तरह से श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष उपस्थित होने के लिए आरक्षित है। उनकी यह टिप्पणी अकाल तख्त कार्यालय द्वारा मंगलवार को मुख्यमंत्री को लिखे पत्र के बाद आई है, जिसमें 15 जनवरी को उनकी उपस्थिति का समय सुबह 10 बजे के बजाय शाम 4:30 बजे कर दिया गया था। मंगलवार को अकाल तख्त कार्यालय द्वारा लिखे गए पत्र का जवाब देते हुए मान ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आदरणीय जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब जी... 15 जनवरी को मेरा कोई अन्य कार्यक्रम नहीं है।

आचार संहिता के बावजूद महायुति को पैसे बांटने की खुली छूट : संजय राउत

मुंबई, (एजेंसी)। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने बुधवार को महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद महायुति की पार्टियों भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट) और एनसीपी को घर–घर जाकर प्रचार और पैसे बांटने की खुली छूट दी जा रही है। मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने कहा कि नियमों के मुताबिक मंगलवार को चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी चुनाव आयोग ने डोर–टू–डोर कैंपेन की अनुमति दे दी, जो सवालों के घेरे में है। राउत ने कहा जब आचार संहिता लागू है और प्रचार खत्म हो चुका है, तब घर–घर जाकर प्रचार की इजाजत देना किस तरह का नियम है? यह सीधे तौर पर भाजपा, एकनाथ शिंदे और अजित पवार को पैसे बांटने का लाइसेंस देने जैसा है। संजय राउत ने मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बिहार में करीब 60 लाख, उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ और पश्चिम बंगाल में लगभग 54 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की कटौती से चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा एक राज्य में लाखों वोटरों के नाम हटाना चुनाव की दिशा बदल सकता है। महाराष्ट्र में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। भाजपा पर निशाना साधते हुए राउत ने कहा कि पार्टी निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं लड़ती। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में हिंदू–मुस्लिम मुद्दा असफल होने के बाद अब मुकाबला ईडी बनाम तृणमूल कांग्रेस में बदल गया है।

सेना प्रमुख द्विवेदी ने गणतंत्र दिवस शिविर का किया दौरा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने बुधवार को दिल्ली छावनी के कारियाप्पा परेड कैंप में आयोजित राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस शिविर 2026 का दौरा किया। इस दौरान, सीओएएस ने राष्ट्रीय आयोजन के लिए चयनित कैडेटों से बातचीत की। शिविर के दौरे के अलावा, जनरल द्विवेदी और एडब्लूडब्ल्यूए की अध्यक्ष सुनीता द्विवेदी ने आर्मी हाउस में कैडेटों का स्वागत किया। कैडेटों से बातचीत करते हुए सेना प्रमुख ने राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने में एनसीसी की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। इसके साथ ही अनुशासन, दृढ़ता, कड़ी मेहनत और नेतृत्व को चरित्र और उत्कृष्टता के आधार स्तंभ बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि हाल की घटनाओं ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारतीय युवा क्या करने में सक्षम हैं। आप जेनरेशन जेड की सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ी आबादी हैं। हमारे युवा शक्ति का भंडार हैं, जिसे अनुशासन, उद्देश्य और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के साथ सही दिशा में ले जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा, ष्ऑपरेशन सिंदूर भारत के संकल्प और संयम का एक निर्णायक प्रदर्शन था, जो हमारे सशस्त्र बलों और युवाओं की नैतिक शक्ति और पेशेवर उत्कृष्टता का प्रतिबिंब था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश भर में 75,000 से अधिक एनसीसी कैडेटों ने स्वेच्छा से नागरिक सुरक्षा, अस्पताल प्रबंधन, आपदा राहत और सामुदायिक सेवाओं में अथक परिश्रम किया। 2025 में, 10 एनसीसी कैडेटों, जिनमें 5 लड़के और 5 लड़कियां थीं, जिनकी औसत आयु मात्र 19 वर्ष थी, ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। मुझे उनसे बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जनरल द्विवेदी ने चयनित मेधावी कैडेटों को सम्मानित किया। वहीं, अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करते हुए उन्हें भारत के मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया। भारतीय सेना ने एक्स पर लिखा–इस संवाद ने कैडेटों को वीरता पुरस्कार विजेताओं और खिलाड़ियों से मिलने का अवसर भी प्रदान किया, जिनमें सूबेदार मेजर और मानद लेफ्टिनेंट संजय कुमार, ओलंपियन होकाटो सेमा और ओलंपियन जैस्मिनी शामिल हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर का एक महीने तक चलने वाला गणतंत्र दिवस शिविर 30 दिसंबर को कारियाप्पा परेड शिविर में पारंपरिक सर्व धाम पूजा के साथ शुरू हुआ। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, शिविर में कई अंतर–निदेशालय प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम शामिल हैं।

संपादकीय

अर्थव्यवस्था की मुश्किलें

प्रधानमंत्री के साथ अर्थशास्त्रियों की बजट पूर्व बैठक में अर्थव्यवस्था की मुश्किलें खुल कर सामने आईं। अर्थशास्त्रियों ने ब्याज चुकाने की बढ़ी देनदारी, कमजोर होती घरेलू बचत, और सरकार के बढ़े पूंजीगत निवेश से आई दिक्कतों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री के साथ बजट पूर्व बैठक में उपस्थित अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था में पैदा हुई मुश्किलों का उल्लेख किया। उन्होंने ब्याज (और ऋण का मूलधन भी) चुकाने की बढ़ती देनदारी, कमजोर होती घरेलू बचत, और सरकार के बढ़े पूंजीगत निवेश के कारण निजी निवेश के सामने आई दिक्कतों का जिक्र किया। कहा कि पूंजीगत निवेश के लिए सरकार अधिक ऋण लेती है, तो निजी निवेशकों के लिए कर्ज महंगा हो जाता है। यह स्वस्थ स्थिति नहीं है। इस क्रम में सरकार पर कर्ज संबंधी देनदारी बढ़ती है। हाल यह है कि केंद्रीय बजट का एक चौथाई से ज्यादा हिस्सा ऋण एवं ब्याज चुकाने पर खर्च हो रहा है। बहरहाल, अर्थशास्त्रियों की बात मान कर सरकार पूंजीगत निवेश घटा दे, तो मौजूदा आर्थिक वृद्धि दर को बनाए रखना फिलहाल कठिन हो जाएगा। निजी निवेश सिर्फ इसलिए नहीं कमजोर पड़ा है कि ऋण महंगा है। बल्कि बाजार में मांग ना होने के कारण निजी क्षेत्र अपनी मौजूदा क्षमता का भी उपयोग नहीं कर पा रहा, तो वह नया निवेश कहां करेगा? खुद अर्थशास्त्रियों ने उल्लेख किया कि घरेलू बचत गिरते हुए जीडीपी के लगभग सात प्रतिशत के बराबर पहुंच गई है। उन्होंने इसकी चर्चा विदेशी पूंजी निवेश को लेकर बढ़े अनिश्चय के संदर्भ में की। कहा कि इस बीच घरेलू बचत भी इतना घट गया है कि वह चालू खाते के दो फीसदी घाटे को पाटने में भी सक्षम नहीं है। मगर घरेलू बचत गिरने का एक दूसरा पहलू भी है। यह संकेत है कि आम परिवारों का बजट दबाव में है। ऐसे में उपभोग एवं मांग में कैसे बढ़ोतरी होगी? यह नहीं हुआ, तो निजी निवेश की स्थितियां कैसे बनेंगी? तो कुल संकेत यह है कि अर्थव्यवस्था एक दुश्चक्र में फंस गई है। इसके बीच सरकार के लिए के लिए पूंजी निवेश घटाना एक जोखिम भरा कदम होगा। सामान्य स्थितियों में अर्थशास्त्रियों की ऋण एवं राजकोषीय घाटे के बीच संतुलन बनाने की सलाह उचित मानी जाती, मगर सवाल है कि मौजूदा हाल में क्या इस पर अमल करना व्यावहारिक होगा? वैसे सरकार ने इस चर्चा से क्या ग्रहण किया, यह तो अगले बजट से ही पता चलेगा।

अमेरिकी मनमर्जी को रोकने के लिए विश्व को एक होना पड़ेगा

उमेश

1995 में एक फिल्म आई थी, गैंबलर। गोविंदा–शिल्पा शेट्टी अभिनीत इस फिल्म का एक गाना उन दिनों बेहद मशहूर हुआ था, "मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी" निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप ने ये गाना नहीं सुना होगा, लेकिन उन्होंने हाल ही में न्यूयार्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में जो कहा है, उसका भावार्थ कुछ यही निकलता है। उन्होंने कहा है, "सिर्फ मेरा दिमाग ही मुझे रोक सकता है। मेरी अपनी नैतिकता और अपना दिमाग। यहीं वे चीजें हैं, जो मुझे रोक सकती हैं। मुझे अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं है और न ही इसकी जरूरत।" तीन जनवरी को वेनेजुएला में की गई अमेरिकी कार्रवाई के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में ट्रंप का इन शब्दों का प्रयोग करना दुनिया के लिए निश्चित तौर पर डरावना है। ट्रंप और उनकी सोच पारंपरिक लोकतांत्रिक मुखौटाबाज राजनीति से अलग है, लिहाजा वे खुलकर ऐसा कह रहे हैं। लेकिन सुपर पावर के रूप में स्थापित होने के बाद से ही अमेरिका की सोच और कार्यशैली ऐसी ही रही है। अमेरिका की सत्ता में दो ही पार्टियों का वर्चस्व है। चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों के राष्ट्रपतियों की कार्यशैली कम से कम विदेश मामलों में एक जैसी ही रही है। ट्रंप खुलकर 'अमेरिका फर्स्ट' की नीति और नीयत का हवाला देते हैं, लेकिन दूसरे राष्ट्रपति ऐसा कहने से बचते रहे हैं। हां, उनके भी कदम हमेशा ऐसा ही रहे हैं। अफगानिस्तान में अमेरिकी कार्रवाई हो, खाड़ी युद्ध हो, सूडान स्थित अमेरिकी दूतावास पर आतंकी हमले के बाद अमेरिकी कार्रवाई हो, वियतनाम का युद्ध हो, ईरान पर कार्रवाई हो, हर जगह अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए कार्रवाई करता रहा है। बेशक उसे कई बार मुंह की खानी पड़ी है। हाल ही में ट्रंप के पूर्व राष्ट्रपति रहे डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन की सेनाएं अफगानिस्तान छोड़कर भाग खड़ी हुईं। वियतनाम का युद्ध लंबा चला था। इसे शुरू किया था डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने और जब अमेरिका वियतनाम युद्ध में फंसता नजर आया तो रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति रहे रिचर्ड निक्सन ने सेनाओं की वापसी कराई। कुवैत पर जब इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन ने हमला किया, तब जार्ज बुश सीनियर राष्ट्रपति थे। अमेरिका में एक धारणा रही है कि कुवैत पर कब्जे की कार्रवाई इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अमेरिकी इशारे पर ही की थी। लेकिन जब मामला उल्टा पड़ गया तो जॉर्ज बुश सीनियर ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों की आड़ में ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों के साथ गठबंधन करके सैनिक कार्रवाई शुरू की। 1990 में अमेरिकी कार्रवाई के चलते इराकी गार्ड को कुवैत को खाली करना पड़ा। इसके बाद इराक अमेरिका का कट्टर दुश्मन बन गया। वैसे लंबे समय तक चले ईरान–इराक युद्ध के पीछे भी अमेरिकी हित काम कर रहे थे। तब दुनिया दो ध्रुवीय थी। एक तरफ सोवियत संघ की अगुआई में विश्व का एक बड़ा हिस्सा काम कर रहा था तो दूसरी ओर अमेरिकी अगुआई में ज्यादातर नाटो देश सक्रिय थे। अफगानिस्तान में जब पिछली सदी के अस्सी के दशक में सोवियत सेनाएं घुसीं, तब सोवियत संघ को काबू करने के लिए अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तान का उपयोग किया और एक तरह से पाकिस्तान को अपना अघोषित उपनिवेश बना लिया। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 1965 और 1971 के युद्धों में अमेरिका में चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, अमेरिकी सेनाओं और सरकार ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान का साथ दिया और भारत का विरोध किया। साल 2024 में हुए बांग्लादेश में विद्रोह और शेख हसीना के तख्तापलट के पीछे भी अमेरिकी एजेंसियों के हाथ को लेकर संदेह जताया जाता है। साल 2010 के दिसंबर में ट्यूनिशिया में शुरू हुई पिंक क्रांति, जिसे अरब क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, की बुनियाद पर अरब देशों में कार्रवाई करने और तख्तापलट के पीछे भी अमेरिकी एजेंसियों के सहयोग को देखा जाता है। अमेरिकी एजेंसियों की ही शह पर लीबिया से गद्दाफी की विदाई हुई, सीरिया अब भी जल रहा है। निश्चित तौर पर अमेरिकी प्रतिकार में शीत युद्ध के दिनों में सोवियत संघ कभी प्रत्यक्ष तो कभी परोक्ष काम करता था, अब दुनिया की दूसरे नंबर की आर्थिक महाशक्ति बन चुका चीन कर रहा है। हाल ही में वेनेजुएला के जिन मादुरो की सत्ता को अमेरिकी सेनाओं ने पलट दिया, उन्हें चीन का खुला समर्थन मिल रहा था। शीत युद्ध के दिनों में सोवियत संघ और उसकी सेना ऐसे हालात में अमेरिकी सेनाओं का परोक्ष विरोध करती थी, वैसा चीन नहीं कर पाया। कह सकते हैं कि अमेरिका में हर सत्ता ने वैश्विक ताकत क्रम में खुद को सर्वोच्च बनाए रखने के लिए अपने हिसाब से दादागिरी दिखाई है।

कभी यह दादागिरी अमेरिकी हितों के नाम पर हुई तो कभी दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर। कहने के लिए अमेरिका लोकतंत्र का सबसे बड़ा पहरूआ बनता है, लेकिन अमेरिकी हितों, कारोबारियों और हथियार लॉबी के हित में अक्सर वह गैर लोकतांत्रिक तरीके से कार्रवाई करता है। दुनिया का आधुनिक इतिहास इससे भरा पड़ा है। वेनेजुएला इसका ताजा उदाहरण है। ट्रंप जिन अंतरराष्ट्रीय कानूनों को अपने हिसाब से मानने या न मानने की बात कर रहे हैं, दरअसल उन्हें बनाने और संशोधित करने में सबसे ज्यादा योगदान अमेरिका का ही रहा है। विश्व में जब भी कहीं वेनेजुएला जैसी घटना होती है, तब जिनेवा समझौते और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का बहुत जिक्र होता है। दरअसल उन्नीसवीं सदी के मध्य तक दुनिया में होने वाले युद्धों के लिए युद्धबंदियों और सैनिकों और युद्धग्रस्त देशों के लोगों को लेकर शत्रु देशों की ओर से की जाने वाली अमानवीय कार्रवाई को रोकने के लिए ना तो कोई कानून था और इसे लेकर कोई प्रयास हुआ था। साल 1864 में पहली बार युद्ध के वक्त घायलों की मदद युद्धरत देशों के बीच बातचीत के लिए रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेंट ने कोशिश की। यही कोशिश पहले जेनेवा समझौते के रूप में सामने आई। इस दौरान युद्धरत देशों, उनके नागरिकों, सैनिकों आदि के मानवीय अधिकारों की रक्षा करने को लेकर चर्चाएं शुरू हुईं। इसके तहत कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परिकल्पना की गई और युद्ध के प्रभाव को सीमित करने और युद्धबंदियों के अधिकारों के संरक्षण की कोशिश शुरू हुई। जेनेवा में आखिरी समझौता 1949 में हुआ। जिनेवा कन्वेंशन का मकसद युद्ध के वक्त मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिये कानून तैयार करना है। 1949 के समझौते में शामिल दो प्रोटोकॉल 1977 में जोड़े गए। आज तकरीबन पूरी दुनिया ने इस पर हस्ताक्षर किया है। इस लिहाज से जेनेवा समझौते को सभी देश मानते हैं। जेनेवा समझौते के अनुसार हर देश की अपनी संप्रभुता है और उसकी रक्षा ना सिर्फ युद्ध बल्कि शांति काल में भी होती है। यानी उसके नियम और कानून युद्ध, शांति और संकट काल, हर वक्त लागू होते हैं। इस संदर्भ में देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह कहना कि उनकी अपनी नैतिकता ही उन्हें किसी भी कार्रवाई से रोक सकती है। ट्रंप ने यहां तक कहा है कि जहां उन्हें लगेगा कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून मानना चाहिए, वहां तो उसे वे मान लेंगे और जहां नहीं लगेगा, वहां नहीं मानेंगे। अमेरिकी दादागिरी के इतिहास में ट्रंप का यह बयान दुनिया की सोच से आगे है। चीन, ब्राजील और भारत के खिलाफ वे टैरिफ युद्ध चला ही रहे हैं, रूस से तेल खरीदने के आरोप की आड़ में वे तीनों देशों पर अब 25 प्रतिशत की बजाय पांच सौ प्रतिशत टैरिफ थोपने की धमकी दे रहे हैं।

चीन को दुश्मन बताकर उसका आर्थिक बहिष्कार करने का ऐलान किय

देश को धर्मांधता और राष्ट्रवाद के जहर में डुबोकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पतंगबाजी और डमरू बजा रहे हैं। जनता को फिर भी समझ नहीं आ रहा कि मदारी जैसे खेल दिखाकर दर्शकों को असलियत से भटका देता है, वही काम भाजपा सरकार कर रही है। मदारी तो फिर भी अपनी रोजी–रोटी के लिए यह काम करता है, उसमें पेशे के प्रति ईमानदारी होती है, जो भाजपा की मौजूदा सरकार में सिरे से नदारद दिख रही है। छह साल पहले जून 2020 में गलवान घाटी पर चीन ने अतिक्रमण की कोशिश की थी और इसमें सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों से झड़प हुई, जिसमें कम से कम 20 जवान शहीद हुए थे। उस समय नरेन्द्र मोदी से बिहार चुनाव में बिहार रेजीमेंट के शहीद जवानों के नाम को भुनाया था। आचार संहिता कहती है कि सेना के नाम पर वोट नहीं मांगे जा सकते, लेकिन नरेन्द्र मोदी कहां आचार–विचार की परवाह करते हैं। उन्हें केवल सत्ता और मुनाफा नजर आता है। इसलिए अब जिस चीन को दुश्मन बताकर उसका आर्थिक बहिष्कार करने का ऐलान किया, लाल आंखें दिखाकर डराने का वादा किया, अब उसी चीन की सत्तारुढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से भाजपा और संघ की बाकायदा बैठक हो रही है। इनकी निर्लज्जता और दुस्साहस अब इतना अधिक हो चुका है कि इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी जा रही है। भाजपा जानती है कि देश का बिका हुआ मीडिया और चापलूसी में लगे पत्रकार इस बारे में कोई आलोचना नहीं करेंगे। बल्कि अब देश को बताया जाएगा कि चीन से नजदीकी बढ़ाकर प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे मास्टर स्ट्रोक चला है। मोदी और जिनपिंग का प्लान, ट्रंप होगा परेशान, जैसी हेडलाइन्स देखने मिलें तो आश्चर्य नहीं।पाठकों को बता दें कि मंगलवार को भाजपा के विदेश मामलों के विभाग के प्रभारी विजय चौथाई वाले ने एक पोस्ट में जानकारी दी कि सीपीसी के अंतरराष्ट्रीय विभाग (आईडीसीपीसी) की उपमंत्री सुन हैयान के नेतृत्व में सीपीसी प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान भाजपा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पार्टी के महासचिव अरुण सिंह ने किया। बैठक में भारत में चीनी राजदूत जू फीहोंग भी शामिल हुए। बैठक के दौरान भाजपा और सीपीसी के बीच संचार और संवाद को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई। अब ये सवाल भाजपा से पूछा जा सकता है कि आखिर वह किस हैसियत से उस देश की सत्तारुढ़ पार्टी से संचार और संवाद बढ़ाना चाहती है, जो बार–बार हमारी सीमाओं में अतिक्रमण करता है, हमारे इलाकों पर अपना दावा ठोंकता है, और जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मदद पहुंचाई? क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा और चीन की पार्टी के बीच हुई बैठक से नावाकिफ थे? अगर नहीं, तो पहले से इस बारे में उन्होंने देश को सूचित क्यों नहीं किया। वैसे प्रधानमंत्री मोदी से अब किसी भी किस्म की ईमानदार पहल की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि गलवान के बाद उन्होंने कहा था कि न कोई घुसा था, न हमारी जमीन गई। जबकि तथ्य है कि चीनी सेना ने हमारी जमीन का अतिक्रमण किया है और अब उसे वापस लेने की मांग शायद भारत सरकार ने छोड़ दी है।देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल हजारों साल पहले के हमलों का बदला लेने के लिए आज के नौजवानों को उकसा रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। पहले कंधार तक वो आतंकवादियों को छोड़कर आए थे, और अब गलवान, पुलवामा, पहलगाम जैसे बड़े हमलों के बावजूद उनकी कोई पुख्ता रणनीति सामने नहीं आ रही है, जिससे पता चले कि हां वो वाकई धुरंधर है। खैर, भाजपा और चीन अब भाई–भाई हैं, ये बात तो भाजपा ने ही साबित कर दी है। इधर चीन ने अपने अतिक्रमण वाले चरित्र को बरकरार रखते हुए जम्मू–कश्मीर की शक्सगाम घाटी पर अपने क्षेत्रीय दावे को दोहराया है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि यह क्षेत्र चीन का हिस्सा है और 1960 के दशक में पाकिस्तान के साथ सीमा समझौते के तहत यह वैध है। उन्होंने भारत की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि चीन और पाकिस्तान को संप्रभु देशों के रूप में सीमा निर्धारण का अधिकार है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि शक्सगाम घाटी भारतीय क्षेत्र है और 1963 का चीन–पाकिस्तान सीमा समझौता अवैध और अमान्य है। बता दें कि पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों से 5,180 वर्ग किमी भूमि चीन को सौंप दी थी। यानी जिस जमीन पर पाकिस्तान ने जबरन हक जमा रखा है, उसे उसने चीन को सौंपा है और अब दोनों इसे सही बता

रहे हैं। लेकिन ये मोदी सरकार की कमजोरी ही है कि जुबानी जमाखर्च से बात आगे नहीं बढ़ रही है। चीन अब शक्सगाम घाटी में सड़क और सैन्य बुनियादी ढांचा विकसित कर रहा है। जो भारत की सुरक्षा के लिए सही नहीं है।सवाल ये है कि क्या गलवान के बाद जैसे मोदी सरकार चुपके से चीन के सामने झुक गई, क्या अब भी वैसा ही होगा। गलवान और पहलगाम के शहीदों के परिजनों पर इस समय क्या बीत रही होगी, ये कल्पना नहीं की जा सकती है। वे तो इसी भरोसे में थे कि भाजपा और नरेन्द्र मोदी जिस तरह भारत माता के लिए अपनी श्रद्धा दिखाते हैं, कम से कम उसकी खातिर ही दुश्मन देश के सामने कायरों की तरह झुकते नहीं। पाठकों को याद दिला दें कि 2020 में भाजपा ने चीनी सामानों के बहिष्कार की मुहिम चलाई थी और उसे राष्ट्रवाद से जोड़ दिया था। अभी कुछ महीने पहले ही नरेन्द्र मोदी ने छोटी–छोटी आंखों वाले गणेश जी नहीं चाहिए, जैसा बयान दिया था। लेकिन हकीकत ये है कि 2020–21 में चीन से हमारा आयात 45 प्रतिशत तक बढ़कर 94.57 बिलियन डॉलर पहुंचा था। भारत–चीन के बीच कुल व्यापार 2020–21 में 86.39 बिलियन डॉलर था जो 2021–22 में बढ़कर 115.83 बिलियन डॉलर हो गया। तो फिर बहिष्कार की बात झूठी ही निकली। अब धीरे–धीरे राष्ट्रवाद का झूठ भी सामने आ रहा है।

स्त्रियों के प्रति कुंद होतीं जन संवेदनाएं

कनुप्रिया एक समय था जब निर्भया के लिये पूरा देश हिल उठा था, उसके प्रति इंसाफ के लिये सड़कों पर आ गया था, सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। यहां तक कि कांग्रेस के सत्ताच्युत होने में निर्भयाकांड एक बड़ा कारण बन गया था, जबकि सरकार ने तुरंत उसका अपने खर्च पर इलाज कराया, आरोपियों को गिरफ्तार किया, फांसी हुई। अभी उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के लिये न्याय की लड़ाई लड़ी ही जा रही है, उन्नाव की पीड़िता के घाव सूखे नही हैं, हाथरस की पीड़िता के साथ हुआ अन्याय आवाज की तलाश में ही है कि कानपुर से 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार की खबर आ गई, इस बार बलात्कारी एक यू ट्यूबर और सब इंस्पेक्टर है। सड़क से बच्ची का अपहरण करके, 2 घण्टे उसके साथ गैंगरेप करने के बाद उसे बुरी हालत में घर के बाहर फेंक दिया गया। पुलिस ने पहले तो प्राथमिकी दर्ज ही नहीं की, बाद में सीनियर पुलिस अफसर तक पीड़िता के परिजन पहुंचे तो रिपोर्ट दर्ज हुई तब तक बलात्कारी पुलिस वाला फरार हो गया।दुरूखद ये भी है कि अब ऐसी खबरें आती हैं तो हम चौंकते भी नहीं, ये हमारी चेतना को झिंझोड़ता ही नहीं। ऐसी घटनाओं का होना मानो हमारे सामाजिक दैनिक दिनचर्या में शामिल हो गया है। आप गूगल करेंगे तो हर दिन स्त्रियों, बच्चियों के प्रति जघन्य अपराध की कोई न कोई खबर मिल ही जायेगी और सबसे ऊपर जिस प्रदेश का नाम मिलेगा वो अपने आप में एक मिनी हिन्दू राष्ट्र है। वहां धर्म के सबसे बड़े ठेकेदारों की डबल इंजन सरकार है।दरअसल पिछले 11 सालों में जिस योजना पर सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया है वो है बलात्कारी बचाओ योजना। बल्कि जिस शिद्दत से बलात्कारियों को प्रोत्साहन दिया गया है, इसे बलात्कारी बनाओ योजना भी कहें तो अतिशयोक्ति नही होगी, दुनिया में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। बलात्कारियों के प्रोत्साहन के लिये उन्हें लगातार जमानत दी जाती है (हाल ही में बलात्कारी बाबा आसाराम को 10 महीने में चौथी बार जमानत मिली और राम रहीम को 15 वीं बार पैरोल)। जेल से बाहर आने पर बलात्कारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है, कभी उनके पक्ष में भगवा झंडों के साथ जुलूस निकाले जाते हैं। कभी उन पर कानून की धार पूरी तरह कुंद हो जाती है, वो ऐसी मार करता है कि अपराधी को चोट ही नहीं लगती। मसलन महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करना) और 354ए (लैंगिक उत्पीड़न) के तहत श्चार्ज फ्रेम्ड हुए, मगर जांच एजेंसियों ने उन्हें कभी गिरफ्तार ही नहीं किया, 2023 से वो जमानत पर हैं, उनकी जमानत का कभी विरोध भी नहीं हुआ। मीडिया ज्यादातर बलात्कार की घटनाओं पर चुप रहता है, चर्चा नहीं करता, मानो यह सामाजिक चिंता का विषय ही नहीं।उधर यौन शोषण के प्रति न्यायालयों का रवैया ये है कि न्याय के लिये पीड़िताओं को न्यायालयों के खिलाफ धारना देने की नौबत आ जाती है। पिछले ही साल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि किसी नाबालिग लड़की के स्तन पकड़ना, उसके पजामे की डोरी तोड़ना और कपड़े उतारने का प्रयास करना, बलात्कार की कोशिश साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ऐसी कई शर्मनाक और महिलाओं को न्याय के लिये हतोत्साहित करती हुई टिप्पणियां पिछले कुछ सालों में विभिन्न प्रदेशों के न्यायालयों ने की हैं, जो समाज में बलात्कारियों को पर्याप्त प्रोत्साहन देती हैं।इस सबके बाद त्रासदी ये है कि पीड़िताओं के खिलाफ ही सोशल मीडिया पर उन्हें मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तोड़ने और उनके संघर्ष के प्रति समाज के भीतर नकारात्मक नजरिया बनाने के लिए अभियान चलाये जाते हैं। मसलन महिला पहलवानों के खिलाफ ऐसा ही अभियान चलाया गया था कि उनका आंदोलन राजनीतिक है, उनके यौन शोषण की बात झूठ है और आरोपी बिल्कुल निर्दोष है इत्यादि इत्यादि। अब एक अभियान उन्नाव की पीड़िता के विरुद्ध चलाया जा रहा है, एआई के जरिए उनके झूठे वीडियो बनाए जा रहे हैं जिनसे जाहिर हो कि वह स्वयं एक बेशरम महिला है और उसने जानबूझ कर आरोपी कुलदीप सेंगर को फंसाया है। राजनीति तिस पर करेले पर नीम चढ़ा यह कि खुद सरकार बहादुर यौन शोषकों और बलात्कारियों के लिये वोट मांगते हैं, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, उनको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं और उनके खिलाफ मामलों पर पूरी तरह चुप्पी मार जाते हैं। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए जघन्य यौन अपराधों पर सरकार ने जिस तरह खामोशी इख्तियार की उससे साबित हुआ कि सरकार किस कध्दर महिलाओं के प्रति संवेदनहीन है।

धार्मिक जलसों का शोर और सर्दी के सितम से मरते लोग

अनिल

शीतलहर, बाढ़ और भीषण गरमी जैसी प्राकृतिक आपदाएं कोई नई परिघटना नहीं है। यह तो पहले से आती रही है और आती रहेंगी। इन्हें रोका नहीं जा सकता। रोका जा सकता है तो इनसे होने वाली जान–माल की तबाही को, जो सिर्फ राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र की ईमानदार इच्छाशक्ति से ही संभव है। ताजा शीतलहर और उससे होने वाली मौतें हमें बता रही हैं कि जब मौसम के हल्के से विचलन का सामना करने की हमारी तैयारी नहीं है।सरकारी स्तर पर धार्मिक जलसों और विभाजनकारी भाषणों के बीच इस समय देश के विभिन्न इलाकों में शीतलहर कहर बरपा रही है, जिससे हर साल की तरह देश के विभिन्न इलाकों से लोगों के मरने की खबरें भी आ रही हैं। अब तक 400 से ज्यादा लोग सर्दी की ठिठुरन से मौत की नींद सो चुके हैं। वैसे इस तरह की खबरें आना कोई नई बात नहीं है। कहीं भूख और कुपोषण से होने वाली मौतें तो कहीं गरीबी और कर्ज के बोझ से त्रस्त किसानों और छोटे कारोबारियों की खुदकुशी और कहीं जातीय व सांप्रदायिक हिंसा में होने वाली मौतों के जारी सिलसिले के बीच हर साल ही सर्दी की ठिठुरन, लू के थपेड़ों और बारिश–बाढ़ से भी लोग मरते ही रहते हैं।मौसम की अति के चलते असमय होने वाली ये मौतें हमारे उस भारत की नग्न सच्चाइयां हैं, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वह तेजी से विकास कर रहा है और जल्द ही दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। ये सच्चाइयां सिर्फ हमारी सरकारों के शशाइनिंग इंडियाश, शभारत निर्माणश श्न्यू इंडियाश श्स्टार्टअप इंडियाश, श्स्टैंडअप इंडियाश श्मैक इन इंडियाश जैसे हवा–हवाई कार्यक्रमों और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाने जैसे गुलाबी दावों की ही खिल्ली नहीं उड़ाती हैं, बल्कि व्यवस्था पर काबिज लोगों की नालायकी और संवेदनहीनता को भी उजागर करती हैं।वैसे सर्दी हमारे नियमित मौसम चक्र का ही हिस्सा है। कड़ाके की सर्दी इसका हल्का सा विचलन भर है। सर्दी और भीषण सर्दी अंत में हमें कई तरह से फायदा ही पहुंचाती है। सबसे बड़ी बात है कि कड़ाके की सर्दी हमें आश्वस्त करती है कि ग्लोबल वार्मिंग उतनी सन्निकट नहीं है, जितना कि अक्सर हम मान बैठते हैं। मौसम की मौजूदा अति भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हर कुछ साल के बाद हमारा इससे सामना होता रहता है– कभी सर्दी में, कभी गरमी में तो कभी बारिश में।ज्यादातर भारतीय इस मायने में खुशनसीब हैं कि उन्हें मौसम की विविधताएं देखने को मिलती हैं। अन्यथा दुनिया में ऐसे कम ही इलाके हैं जहां हर मौसम का मजा लिया जा सके। प्रत्येक मौसम अपने रौद्र रूप में भी सुंदर होता है, बशर्ते कि उसकी मार से लोगों को बचाने के इंतजामात हों। दुनिया में संभवतरू भारत ही ऐसा देश है, जहां हर मौसम की अति होने पर लोगों के मरने की खबरें आने लगती है। हकीकत यह है कि लोग मौसम की अति से नहीं मरते, वे मरते हैं अपनी गरीबी से, अपनी साधनहीनता से और व्यवस्था तंत्र की नाकामी या लापरवाही की वजह से। यूरोप के देशों में सरकारें मौसम की अति का मुकाबला करने के चाक–चौबंद इंतजाम करती हैं, इसलिए वहां लोग हर मौसम का तरह–तरह से लुत्फ उठाते हैं। हमारे देश में भी खाया–अघाया तबका ऐसा ही करता है, जिसके पास हर मौसम की अति का सामना करने और उसका लुत्फ उठाने के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं।भारत के ज्यादातर हिस्सों में यूरोप जैसी ठंड नहीं पड़ती, लेकिन हमारे यहां जब हिमालय परिवार की पहाड़ियों पर गिरने वाली बर्फ से मैदानी इलाकों में शीतलहर चलती है तो देश के विभिन्न इलाकों में सर्दी की ठिठुरन से होने वाली मौतों के आंकड़े आने लगते हैं। अभी जो शीतलहर जारी है, वह सिर्फ हिमालयी प्रदेशों और गंगा–यमुना के मैदानों तक ही सीमित नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और रेगिस्तानी राजस्थान के साथ ही महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और सुदूर छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा तक ठंड से ठिठुर रहे हैं। सर्दी के इस सितम से सामान्य जनजीवन बुरी तरह गड़बड़ा गया है। देश के विभिन्न इलाकों से बेघर लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। हालांकि बड़े शहरों से निकलने वाले समाचारपत्रों में अब सर्दी से होने वाली मौतों की खबरों को जगह मिलनी लगभग बंद हो गई है। कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था। तब अखबारों में नियमित खबरें छपती थी और हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट उन खबरों का संज्ञान लेकर संबंधित राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों से जवाबतलब करते थे। उन्हें साधनहीन लोगों के उचित इंतजाम करने के निर्देश देते थे। अब सरकारों का मीडिया प्रबंधन तंत्र ऐसी खबरों को छपने से रोकने मे सफल होने लगा है। यही वजह है कि अब कुछ गिने–चुने अखबारों में ही सर्दी से लोगों के मरने की खबरें छपती हैं। टेलीविजन चौनल तो सुबह से रात तक हिंदू–मुसलमान करने में ही व्यस्त रहते हैं। अगर थोड़ी फुरसत मिलती भी है तो उनके लिए अपने दर्शकों को यह बताना ज्यादा जरूरी होता है कि फलां अभिनेत्री कब शादी करने वाली है, फलां अभिनेत्री कब मां बनने वाली है और किस अभिनेत्री का किस अभिनेता से तलाक होने वाला है या फिर वे यह बताते हैं कि लोग सर्दी का लुत्फ लेने के लिए क्या–क्या कर रहे हैं और कहां–कहां जा रहे हैं।सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल औसतन 800 से ज्यादा लोग सर्दी के सितम से मरते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2015 में 1149 लोगों की मौत हुई थी। हकीकत यह है कि अगर समूचे भारत के आंकड़े इकत्रे किए जाएं तो हर साल सर्दी से मरने वालों की संख्या हजारों में पहुंचती है। ज्यादातर मौतें बड़े शहरों और महानगरों में होती हैं। जो मरते हैं, उनमें से ज्यादातर बेघर होते हैं। ऐसे लोग काम की तलाश में दूरदराज के इलाकों से अपने ही राज्य में या दूसरे राज्यों के बड़े शहरों या महानगरों में जाते हैं, ताकि मेहनत–मजदूरी कर अपने परिवार के जिंदा रह सकने लायक कुछ कमा सकें। मौसम कोई भी हो, जब भी उसकी अति दरवाजे पर दस्तक देती है तो हमारी सारी व्यवस्थाओं की पोल का पिटारा खुलने लगता है। फिलहाल सर्दी की बात की जाए तो हमेशा की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा पोल खुली है पूर्वानुमान लगाने वाले मौसम विभाग की। बारिश का मौसम खत्म होते ही हमें बताया गया था कि इस बार सर्दी कम पड़ेगी। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की चर्चाओं के बीच इस भविष्यवाणी पर किसी को भी हैरानी नहीं हुई थी, परन्तु जैसे ही सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए तो फिर मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि यह कड़ाके की ठंड चंद दिनों की ही मेहमान है। जल्द ही मौजूदा उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख बदलेगा और तापमान सामान्य के करीब पहुंच जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ मौसम विभाग ही नहीं, बाकी सरकारी महकमों का भी यही हाल है। फुटपाथों, रेलवे स्टेशनों और भूमिगत पारपथों पर रात गुजारने वाले बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था अभी भी कई जगह अधूरी है या बिल्कुल ही नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट पूर्व में कई बार इस मामले में राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए पुख्ता बंदोबस्त करने के निर्देश दे चुका है। जहां रैन बसेरों की व्यवस्था करना संभव नहीं है, वहां अलाव जलाने के लिए लकड़ी मुहैया कराई जाती है, लेकिन यह भी नहीं हो पा रहा है। दरअसल शहरी और अर्द्ध शहरी इलाकों में मौसम की मार से लोगों के मरने के पीछे सबसे बड़ी वजह है शहरी नियोजन में सरकारी तंत्र की अदूरदर्शिता। जब से आवासीय कॉलोनियों की बसाहट के मामले में विकास प्राधिकरणों और गृह निर्माण मंडलों के बजाय निजी भवन निर्माताओं और कॉलोनाइजरों का दखल बढ़ा है, तब से रोज कमाकर रोज खाने वालों और बेघर लोगों के लिए आवासीय योजनाएं हाशिए पर खिसकती गई हैं। करोड़ों लोग आज भी फुटपाथों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर और टाट या प्लास्टिक आदि से बनी झोपड़ियों में रात बिताते हैं।

हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के किसी भी तरह के समायोजन पर लगाई रोक

लखनऊ, (संवाददाता)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को प्राथमिक शिक्षकों के समायोजन –3 मामले में आगे किसी कार्यवाही पर 19 जनवरी तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को नियत करके अंतरिम आदेश दिया कि मामले की इस अगली सुनवाई की तिथि तक बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर, समायोजन –3 मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं करेंगें। कोर्ट ने कहा कि इस अंतरिम आदेश की राहत, इस याचिका के साथ संबद्ध 11 अन्य याचिकाओं के याची शिक्षकों को भी उपलब्ध होगी। कोर्ट ने यह आदेश प्राथमिक शिक्षकों के समायोजनध स्थानांतरण – 3 के शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिया। न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश बाराबंकी की संगीता पाल समेत 29 प्राथमिक शिक्षकों की याचिका पर दिया। याचिकाओं में 14 नवंबर 2025 के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी शिक्षकों के समायोजनध स्थानांतरण के शासनादेश को चुनौती देकर रद्द करने का आग्रह किया गया है। याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एच जी एस परिहार का कहना था कि यह शासनादेश आर टी ई अधिनियम समेत बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1981 के नियमों का उल्लंघन करने वाला है। इसके नियम 21 के तहत शिक्षक की सहमति के बाहर समायोजित न किए जाने की दलील दी। कहा इस समायोजन से जहां शिक्षकों की वरिष्ठता पर असर पड़ रहा है, वहीं अन्य विसंगतियां भी पैदा हो रही हैं। उधर, मामले में राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता के आग्रह पर कोर्ट ने मामले को 19 जनवरी को फाइनल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस बीच याचियों को मामले में अंतरिम राहत प्रदान की है। साथ ही राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने का समय दिया है।

यौन शोषण-धर्मांतरण के आरोपी डॉ. रमीज के खातों में हुआ संदिग्ध लेनदेन

लखनऊ, (संवाददाता)। यौन शोषण और धर्मांतरण के आरोपी डॉ. रमीज के खाते में संदिग्ध खातों से लाखों के लेनदेन की बात सामने आई है। रमीज के खाते में दिल्ली, आगरा, उत्तराखंड और पीलीभीत समेत कई शहरों से रकम भेजी गई है। आरोपी का पूर्वांचल कनेक्शन भी सामने आया है। जिन खातों से रमीज को रकम भेजी गई थी, उनका ब्योरा पुलिस जुटा रही है। सूत्रों का कहना है कि यह रकम रमीज को धर्मांतरण गिरोह की ओर से भेजी गई थी। पुलिस अब आरोपी और उसके परिजनों की संपत्ति का ब्योरा जुटा रही है। माना जा रहा है कि रमीज के जरिये धर्मांतरण कराने वाले लोगों को पैसे भिजवाए जाते थे। आरोपी के आतंकी संगठनों से कनेक्शन सामने आने के बाद खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। यह पता लगाया जा रहा है कि रमीज ने कितनी बार जम्मू कश्मीर की यात्रा की है। आरोपी के नेपाल कनेक्शन भी खंगाले जा रहे हैं। केजीएमयू से भागने के बाद रमीज 16 दिन तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। इतने दिनों में वह कितने लोगों के संपर्क में रहा और किन लोगों से मदद ली, इसकी दिशा में भी छानबीन की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस से छिपकर रहने के दौरान आरोपी ने विभिन्न संगठनों से फंड भी जुटाए थे। वह पूर्वांचल में अपने करीबियों के ठिकाने पर ठहरा था। पुलिस बहराइच और बलरामपुर में छांगुर बाबा के करीबियों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को संरक्षण देने वालों के बारे में पता लगाया जा रहा है। ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी,।

संक्षिप्त खबरें

साइबर अपराध के प्रति किया जागरूक

लखनऊ, (संवाददाता)। वीमेन पावर लाइन 1090 चौराहे पर मंगलवार को 15 दिवसीय साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान सबकी नीयत साफ नहीं होती का शुभारंभ हुआ। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट और पीरामल फाइनेंस लिमिटेड के आयोजन में नुक्कड़ नाटक से साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया गया। इससे पहले 1090 सभागार में हुई प्रेसवार्ता में साइबर क्राइम से बचने के उपाय बताए गए। अपर पुलिस उपायुक्त (साइबर क्राइम) किरण यादव ने कहा कि तकनीक का दुरुपयोग रोकने के लिए साइबर साक्षरता जरूरी है। ओटीपी फ्रॉड, फेक कॉल, सोशल मीडिया हैकिंग जैसे खतरों के प्रति सचेत करने के लिए अभियान शुरू गया है। पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार सेंगर ने बढ़ती डिजिटल निर्भरता के साथ जुड़े जोखिमों के प्रति आगाह किया। पीरामल फाइनेंस के मुख्य विपणन अधिकारी अरविंद अय्यर ने बताया कि प्रमुख बाजारों, चौराहों और भीड़भाड़ वाले 45 स्थानों पर नुक्कड़ नाटक से लोगों को जागरूक किया जाएगा। सोशल मीडिया कैंपेन और वीडियो के जरिए भी लोगों को संदेश दिया जाएगा। संयुक्त पुलिस आयुक्त अपर्णा कुमार, पुलिस उपायुक्त कमलेश दीक्षित आदि मौजूद रहे।

बैंक मित्र ने की दगाबाजी 24 लोगों से ठगे 50 लाख

लखनऊ, (संवाददाता)। पारा मोहान रोड स्थित शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय परिसर में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में तैनात बैंक मित्र ने करीब 50 लाख रुपये की ठगी कर ली। ठगी का खुलासा होते ही ग्राहकों ने बैंक में मंगलवार को हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी बैंक मित्र व ग्राहकों को लेकर थाने पहुंची। वहां आक्रोशित लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। सरोसा भरोसा निवासी लवकुश पाल ने बताया कि उनके पिता का खाता इसी शाखा में है। बैंक मित्र शिवा राव ने 12 लाख 40 हजार रुपये की एफडी कराई थी। 19 फरवरी को बहन की शादी है। इसके लिए रकम निकालने बैंक पहुंचे तो एफडी फर्जी निकली। इसी तरह सलेमपुर पतौरा निवासी फूलचंद्र के पांच लाख, खुशहालगंज निवासी नूरजहां के ढाई लाख रुपये सहित अवधेश, राम नरेश, हरिशंकर समेत करीब 24 लोगों से 50 लाख से अधिक की ठगी की गई है। शाखा प्रबंधक हिमांशु कुकरेती ने बताया कि कई ग्राहकों ने वित्तीय अनियमितता की शिकायत की थी। जांच में बैंक मित्र राजाजीपुरम निवासी शिवा राव को दोषी पाया गया है। कितने ग्राहकों से धोखाधड़ी हुई है, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि आरोपी और ग्राहकों की बातचीत में आरोपी ने रकम लौटाने की बात कही है। फिलहाल लोगों को समझा–बुझाकर शांत कराया गया है।

एसआईआर की ढिलाई पर चुनाव आयोग सख्त, 8 विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ किए गए तलब आए इतने नए आवेदन

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यों में लापरवाही पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने सख्त रुख अपनाया है। बुक अ कॉल विद बीएलओ योजना के तहत 48 घंटे के भीतर मतदाताओं की समस्याओं का निस्तारण अनिवार्य होने के बावजूद आठ विधानसभा क्षेत्रों में 10 से अधिक प्रकरण लंबित पाए गए। इस पर सीईओ ने संबंधित सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) से स्पष्टीकरण तलब किया है। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीईओ नवदीप रिणवा ने प्रदेश के सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप निर्वाचन अधिकारियों और ईआरओ के साथ एसआईआर कार्यों की समीक्षा की। जिन आठ विधानसभा क्षेत्रों में 48 घंटे से अधिक समय से 10 से ज्यादा मामले लंबित मिले, उनमें मुरादाबाद ग्रामीण, शिकोहाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, चायल, मधुबन, कुंदरकी, मनकापुर और मुरादाबाद नगर शामिल हैं। सीईओ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बूथवार नियमित समीक्षा हो और किसी भी स्थिति में कोई भी प्रकरण 48 घंटे से अधिक लंबित न रहने पाए। सीईओ ने सभी जिलों को निर्देशित किया कि 18 जनवरी को दोबारा प्रत्येक बूथ पर ड्राफ्ट मतदाता सूची सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाए। इस कार्य में राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए), ग्राम प्रधान और पार्षदों का सहयोग लिया जाए। मतदाता जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बीएलओ के पास फॉर्म–6, फॉर्म–7 और फॉर्म–8 की पर्याप्त उपलब्धता रहे। ऑफलाइन फॉर्म–6 भरने वाले मतदाताओं से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में विवरण भरवाया जाए।

अल्टीमेटम बेअसर, न हुई एफआईआर ना होगी हड़ताल

लखनऊ, (संवाददाता)। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में प्रस्तावित हड़ताल फिलहाल नहीं होगी। शासन ने केजीएमयू प्रशासन से नौ जनवरी को हुई घटना के और सबूत मांगे हैं। नौ जनवरी को कुलपति कार्यालय पर हुए हंगामे और तोड़फोड़ के बाद केजीएमयू के पांचों संगठन ने एफआईआर न होने पर हड़ताल की चेतावनी दी थी। शासन और केजीएमयू प्रशासन से हुई वार्ता के बाद फिलहाल सभी कार्य बहिष्कार न करने के लिए तैयार हो गए हैं। केजीएमयू में धर्मांतरण के प्रयास का मुद्दा गर्माया हुआ है। इसी मामले में नौ जनवरी को राज्य महिला आयोग की आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के केजीएमयू पहुंचने के बाद जमकर हंगामा हुआ था। अपर्णा यादव के समर्थकों और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कुलपति कार्यालय में भी हंगामा किया था। इस दौरान तोड़फोड़ भी हुई थी। केजीएमयू शिक्षक संघ, कर्मचारी संघ, नर्सिंग एसोसिएशन, रेजिडेंट एसोसिएशन और एससी–एसटी कार्मिक संगठन ने इस पर आक्रोश जताते हुए मंगलवार को हड़ताल की घोषणा की थी। कुलपति के अनुरोध पर प्रस्तावित कार्य बहिष्कार एक दिन के लिए टाला गया था। इस बीच मंगलवार को शासन ने घटना के संबंध में केजीएमयू प्रशासन से और सबूत मांगे। ऐसे में कुलपति की अपील पर सभी संगठन फिलहाल कार्य बहिष्कार टालने के लिए तैयार हो गए। सूत्रों का कहना है कि महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने नौ जनवरी को हुई मुलाकात में मुख्यमंत्री को केजीएमयू अकेले जाने की बात बताई है। वहीं, केजीएमयू प्रशासन की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर में अपर्णा यादव के साथ आए समर्थकों की ओर से हंगामा और प्रदर्शन करने की बात कही गई है। इसी को देखते हुए शासन ने अतिरिक्त सबूत मांगे हैं। केजीएमयू प्रशासन की ओर से घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग शासन को भेजे गए हैं। प्केजीएमयू के सभी डॉक्टर और कर्मचारी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। नौ जनवरी को हुई घटना के संबंध में कुलपति की मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव गृह से वार्ता हुई है।

ग्रीन कॉरिडोर को किसान पथ से जोड़ने के दौरान शहीद पथ पर चलता रहेगा ट्रैफिक

लखनऊ, (संवाददाता)। ग्रीन कॉरिडोर को किसान पथ से जोड़ने के दौरान शहीद पथ पर आवागमन बाधित नहीं होगा। निर्माण कार्य चलते रहने के बावजूद शहीद पथ पर ट्रैफिक सामान्य रूप से चलता रहेगा। समतामूलक से निशातगंज चौराहे तक ग्रीन कॉरिडोर शुरू होने के बाद जाम की स्थिति न बने, इसके लिए कुछ स्थानों पर यू–टर्न दिए जाएंगे और उनका ट्रायल भी कराया जाएगा। यह निर्णय मंगलवार को एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार की अध्यक्षता में ग्रीन कॉरिडोर परियोजना और यातायात पुलिस के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिया गया। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के द्वितीय चरण के तहत पक्का पुल से समतामूलक चौराहे तक बंधा रोड, 6–लेन ब्रिज, फ्लाईओवर और आरओबी का निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत समतामूलक, निशातगंज और हनुमान सेतु पर तीन नई रोटरी बनाई गई हैं। भविष्य में इस रूट के शुरू होने पर इन चौराहों पर ट्रैफिक बाधित न हो, इसे लेकर बैठक में ग्रीन कॉरिडोर योजना की प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट के प्रभारी एके सिंह सेंगर ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के सुझाव पर हनुमान सेतु रोटरी का ड्रोन सर्वे कराया गया। यह सर्वे लगातार दो दिनों तक सुबह 10 और शाम 6 बजे के पीक ऑवर्स में किया गया, जिसमें रोटरी पर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू पाई गई। प्रोजेक्ट प्रभारी ने बताया कि निशातगंज और समतामूलक रोटरी पर ट्रैफिक जाम की आशंका को देखते हुए मौके पर परीक्षण किया गया। यातायात विभाग ने कुछ स्थानों पर सीधे मार्ग के बजाय यू–टर्न की व्यवस्था करने का सुझाव दिया है। इसके लिए ट्रायल कराया जाएगा। ट्रायल के नतीजों के आधार पर रूट खोलने से पहले आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि ग्रीन कॉरिडोर के तृतीय और चतुर्थ चरण में समतामूलक चौराहे से किसान पथ तक बंधा रोड, फ्लाईओवर और ब्रिज का निर्माण किया जाना है। इसके तहत शहीद पथ पर इकाना स्टेडियम के पास फ्लाईओवर बनाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य के दौरान शहीद पथ पर ट्रैफिक बंद नहीं किया जाएगा, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि कार्य शुरू होने से पहले लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और यातायात पुलिस के अधिकारियों के साथ संयुक्त सर्वे भी कराया जाएगा।

संक्षिप्त खबरें

ग्रीडी प्रिंटिंग से मॉडल बनाकर दिखाया कौशल

लखनऊ, (संवाददाता)। अलीगंज स्थित राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहित राजधानी के नौ शिक्षण संस्थानों में मंगलवार को दो दिवसीय राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोतिया के पहले चरण का समापन हुआ। प्रतिभागियों ने चार घंटे की लिखित और प्रयोगात्मक परीक्षा में कौशल प्रतिभा दिखाई। बरेली के देव गोस्वामी ने बताया कि प्रयोगात्मक परीक्षा में थ्रीडी प्रिंटिंग से मॉडल बनाया। अयोध्या से आए महिपाल गंगवार ने कहा कि परीक्षा अच्छी हुई। उम्मीद है कि राष्ट्र स्तरीय कौशल प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर मिलेगा। कौशल गविभाग के मिशन निदेशक पुलकित खरे ने राजकीय महिला आईटीआई का निरीक्षण करने के साथ प्रतिभागियों से संवाद किया। इन विषयों और कौशल की हुई प्रतियोगिता रू 16 कार्यशालाओं में 18 मंडलों से आए 451 युवाओं ने तकनीक नवाचार और कौशल दक्षता को प्रदर्शित किया। मुख्य रूप से जिन विषयों व कौशल की प्रतियोगिता हुई उनमें इलेक्ट्रानिक्स, फैशन टेक्नोलॉजी, सीएनसी टर्निंग, वेल्डिंग, सीएनसी मिलिंग आदि शामिल थे।

`आखरी ताजदार' में उतरा नवाब वाजिद अली शाह का किरदार

लखनऊ, (संवाददाता)। भारतीय नारी सम्मान एवं बाल विकास संस्थान की ओर से उर्दू नाटक 'आखरी ताजदार' के मंचन में लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह का किरदार निखरकर सामने आया। नाटक से यह दिखाने की कोशिश की गई कि किस तरह अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह और अवध को धोखा दिया। नवाब ने अंग्रेजों के उस मुहायदे पर दस्तखत करने से इन्कार कर दिया, जिसमें वह चाहते थे कि नवाब वाजिद अली शाह बादशाह बने रहें, लेकिन जनता पर हुक्म अंग्रेजों का चले। नवाब मसूद अब्दुल्लाह के लेखन और निर्देशन से सजे नाटक में दिखाया गया कि नवाब वाजिद अली शाह के कोलकाता चले जाने के बाद बेगम बेगम हजरत महल ने वतन के लिए फर्ज निभाते हुए बेटे शहजादा बिरजीस कद्र को बहादुर सिपहसालारों के साथ मिलकर अवध का ताजदार मुकर्रर कर दिया। सह निर्देशन संजय त्रिपाठी ने किया। नवाब वाजिद अली शाह की भूमिका निभाई नवाब मसूद अब्दुल्लाह ने। नाटक रंगकर्मी स्व. विनय श्रीवास्तव को समर्पित किया गया। अवसर पर लखनऊ की विरासत, संस्कृति और रंगमंच को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए नवाब मसूद अब्दुल्लाह को अवध सम्मान से नवाजा गया।

मोबाइल लूट के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर दिया धरना

लखनऊ, (संवाददाता)। मोबाइल लूट के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर मंगलवार को मऊ गांव की प्रधान विजय लक्ष्मी ने समर्थकों के साथ थाने के गेट पर बैठकर धरना दिया। प्रधान ने बताया कि देवर से लूटा हुआ एक मोबाइल 18 दिसंबर को पुलिस ने बरामद किया था, लेकिन उनके पति का मोबाइल नहीं मिला है। आरोप है कि पुलिस ने मोबाइल बरामद किया, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस आरोपियों को बचा रही है। वहीं, इंस्पेक्टर मलिहाबाद सुरेंद्र सिंह भाटी की ओर से कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद शाम को धरना समाप्त कर दिया गया। 14 दिसंबर को ग्राम प्रधान लक्ष्मी के गांव में देवस्थान पर टिनशेड डलवाने के दौरान मारपीट हुई थी। इसमें गांव के 27 नामजद व 25 अज्ञात समेत 52 लोगों पर मारपीट सहित गंभीर धाराओं दर्ज कराई गई थी। गांव के विमलेश, शैलेंद्र पर मोबाइल फोन लूटने का आरोप था।

लखनऊ में जाम से राहत के लिए बनेगा नया ट्रैफिक प्लान

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा जनपद लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राजधानी में लगातार गंभीर होती जा रही यातायात जाम की समस्या पर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को ठोस और व्यावहारिक ट्रैफिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ में वाहनों की संख्या और आबादी दोनों में तेजी से वृद्धि हो रही है। प्रदेश की राजधानी होने के कारण प्रतिदिन बड़ी संख्या में बाहरी जनपदों से भी वाहन शहर में प्रवेश करते हैं, जिससे जाम की स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। ऐसे में सभी प्रमुख चौराहों का संबंधित अधिकारी स्थलीय निरीक्षण कर स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रभावी योजना तैयार करें, ताकि आम जनमानस को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। प्रभारी मंत्री बटलर रोड स्थित नैमिषारण्य गेस्ट हाउस में माननीय जनप्रतिनिधियों, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त तथा पुलिस अधिकारियों के साथ यातायात व्यवस्था और प्रदेश की मतदाता सूची में चल रहे विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर बैठक कर रहे थे। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार लगातार अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर कार्य कर रही है, लेकिन वर्तमान संसाधनों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी शहर को जाम से राहत दिलाने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जाम वाले क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण किया जाए और मौके पर ही आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। इसी क्रम में उन्होंने विधानसभा के गेट नंबर 7 और 8 के सामने सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बड़े वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश भी दिए।सुरेश कुमार खन्ना ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि यातायात विभाग, लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त कमेटी गठित की जाए। यह कमेटी शहर के उन सभी स्थलों का स्थलीय निरीक्षण करेगी, जहां बार–बार जाम की समस्या सामने आती है। निरीक्षण के आधार पर डायवर्जन, बैरिकेडिंग, वन–वे व्यवस्था जैसे विकल्पों पर विचार करते हुए एक व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार की जाएगी और उस पर अमल सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि जाम की समस्या का स्थायी समाधान निकल सके।बैठक में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भी चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से अपील की कि वे मतदाताओं को जागरूक करें और लोगों को अपने नाम मतदाता सूची में जांचने के लिए प्रेरित करें। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची में छूट गया हो तो उससे फॉर्म–6 और घोषणा पत्र भरवाकर जमा कराया जाए। यह सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्धा है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए यह जरूरी है कि कोई भी पात्र नागरिक वोटर लिस्ट से वंचित न रहे।इसके बाद वित्त मंत्री ने 'विकसित भारत–जी राम जी कानून 2025' पर प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि यह विधेयक विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप एक नई सांविधिक संरचना के साथ मनरेगा का स्थान लेगा। यह कानून रोजगार, पारदर्शिता, योजना और जवाबदेही को मजबूत करते हुए मनरेगा की संरचनात्मक कमियों को दूर करने का प्रयास है। जी राम जी योजना के तहत प्रति ग्रामीण परिवार रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा और अधिक सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि वीबी–जी राम जी एक्ट लागू होने तक मनरेगा पूरी तरह प्रभावी रूप से लागू रहेगी और रोजगार की गारंटी जारी रहेगी।सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि नई योजना के तहत रोजगार सृजन को चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से जोड़ा गया है, जिनमें जल सुरक्षा और संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संवर्धन तथा जलवायु परिवर्तन और प्रतिकूल मौसम से निपटने वाले कार्य शामिल हैं।

मरीजों से मनमानी पर न नोटिस न कार्रवाई

लखनऊ, (संवाददाता)। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय की ओपीडी में मरीजों को खुलेआम बाहर से दवाएं लिखी जा रही हैं। इसके बावजूद न तो डॉक्टरों को कोई नोटिस जारी किया जा रहा है और न ही कार्रवाई हो रही है। इस वजह से गरीब मरीज लूटे जा रहे हैं। केजीएमयू में एक के बाद एक हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड के 22 स्टोर खोले जा चुके हैं। मरीजों के लिए ये स्टोर सहूलियत से ज्यादा समय की बर्बादी की वजह साबित हो रहे हैं। सस्ती दवाओं के लालच में मरीज या उनके तीमारदार एचआरएफ के स्टोर पर लाइन लगाते हैं। एक घंटे बाद नंबर आने पर बताया जाता है कि ज्यादातर दवाएं स्टोर से बाहर की हैं। उनका विकल्प देने पर डॉक्टर दवाएं वापस करा देते हैं। मजबूरी में मरीजों को बाहर से ही महंगी कीमत पर दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। केजीएमयू प्रशासन को भी इसकी सच्चाई पता है, लेकिन अभी तक एक भी डॉक्टर को न तो नोटिस जारी किया गया और न ही कोई कार्रवाई ही हुई। इसका नतीजा है कि मरीज महंगी दवाएं लेने को मजबूर हैं। माल रोड जेहटा से पहुंची सुनीता गुप्ता ने बताया कि एचआरएफ काउंटर पर परचे पर लिखीं सभी दवाओं पर टिक लगाकर दे दिया गया, जबकि दो दवाएं नहीं थीं। इन दो दवाओं के स्थान पर दो गलत दवाएं दे दी गईं। जब आज दोबारा डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि दवाई गलत दी गई है। अब दवा बदलवानी पड़ी। फैजुल्लागंज निवासी निशा शुक्ला मेडिसिन विभाग की ओपीडी में दिखाने आई थीं। एचआरएफ काउंटर के बाहर निशा शुक्ला ने बताया कि उन्हें एक भी दवा नहीं मिली। बोला गया कि बाहर मेडिकल स्टोर से ले लें। सीतापुर के लालपुर से आईं पूजा ने बताया कि वह 10 दिन से लगातार आ रही हैं, लेकिन दवाएं नही मिल पा रही हैं।

पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने केक काटकर और कंबल वितरण कर मनाया डिंपल यादव का जन्मदिन

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव का जन्मदिन अपने आवास पर बड़ी धूमधाम से मनाया।इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने केक काटकर और महिलाओं को कंबल वितरित कर उनके दीर्घायु होने की कामना की।इस मौके पर पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने कहा कि आज भाजपा के शासन में बहन बेटियों और महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है।उन्होंने कहा अखिलेश यादव की सरकार ने बहन बेटियों के लिए कन्या विद्या धन की योजना शुरू की थी लेकिन आज भाजपा के शासन में सब बंद हो चुका है।इस मौके पर उन्होंने कहा आज प्रदेश में किसान नौजवान व्यापारी सभी परेशान हैं इस सरकार में नौकरी खत्म हो चुकी है आज प्रदेश की जनता फिर से प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनाने के लिए आतुर है।उन्होंने 2027 के चुनाव मे अखिलेश यादव की सरकार बनाने का आवाहन किया।इस मौके पर ने वहाँ पर मौजूद लोगो ने एक स्वर में प्रदेश में फिर से अखिलेश यादव की सरकार बनाने का संकल्प लिया जिससे प्रदेश में फिर से अमन चौन खुशहाली और तरक्की हो सके महानगर प्रवक्ता राकेश यादव एडवोकेट ने बताया इस मौके पर निवर्तमान जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव, प्रवक्ता राकेश यादव एडवोकेट, विधानसभा अध्यक्ष रक्षा राम यादव,नि 0 महासचिव गोपीनाथ वर्मा, पूर्व प्रधान गयादीन यादव प्रधान राजेश कोरी, अली सईद अहमद, शमशेर यादव, ब्लॉक अध्यक्ष तरजीतगोड़, वंशराज चौरसिया, राजेश यादव, प्रमोद मिश्रा, घनश्याम मिश्रा, पवन तिवारी, राम शंकर वर्मा रामशंकर तिवारी चौतराम यादव सुखदेव यादव, अनिल तिवारी, शादाब खान, नूर बाबू, बबलू पांडे, जयराम मिश्रा, अनिल तिवारी, मुंशी वर्मा, सूबेदार यादव, राजेश वर्मा, राकेश तिवारी, पंकज शर्मा, बलराम पांडे, हनुमान पांडे, प्रेम पांडे, चंद्र प्रकाश तिवारी, रघुनाथ वर्मा, आसाराम निषाद, चंद्र प्रकाश निषाद आदि लोग मौजूद रहे।

'शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महा पीठ के प्रदेश अध्यक्ष किशन लाल सिंह का धूमधाम से जन्म दिवस मनाया गया'

मुरादाबाद गुरु रवि शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महावीर के प्रदेश अध्यक्ष किशन लाल सिंह का धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया यह कदम उनका उत्तर प्रदेश गुरु रविदास विश्व महा पीठ के बढ़ते कदम के रूप से देखा जा रहा है राज्य की राजनीति में उनकी भूमिका हमेशा अहम मानी गई है बीते बीस वर्षों से संगठन में उनके पास कोई औपचारिक जिम्मेदारी नहीं थी लेकिन हाल ही में बढ़ते कदम को जनजाति तक पहुंचा जा रहा हैं और उन्होंने बताया की गुरु शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महा पीठ उत्तर प्रदेश में गुरु रविदास जी का जन्म दिवस पूरे वर्ष धूमधाम से मनाया जाएगा इस मौके पर क्षेत्र के विभिन्न गण मान्य लोग मौजूद रहेऔर किशनलाल सिंह समाज की सेवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं उनका कार्य पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद रविदास समाज में मजबूत पकड़ है शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महा पीठ राष्ट्रीय और प्रदेश की कमेटी उनको जन्म दिवस पर बधाई दिया उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चरण सिंह लिसाड़ी, जी शेर सिंह जी। सिटी ऑटो रिक्शा यूनियन करवा के उपाध्यक्ष राकेश कुमार, महामंत्री ओमकार चौहान, कपिल त्यागी कोषाध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह रावत, महेंद्र सिंह, नवनीत कठेरिया आदि।

संक्षिप्त खबरें

महिला एसओ के प्रयास से काफी दिनो से अलग रह रहे पति-पत्नी आपस में रहने को हुए राजी

अयोध्या। बुधवार को महिला थाना पुलिस के काफी प्रयास के बाद कई माह से एक दूसरे से अलग रह रहे पति पत्नी फिर साथ साथ रहने को तैयार हुए।इस संबंध में महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला ने बताया कि तबस्सुम काल्पनिक नाम पत्नी मोहम्मद अंसार निवासी मुबारक गंज थाना रौनाही जनपद अयोध्या ने इस संबंध में महिला थाना मे प्रार्थना पत्र दिया था। बताया कि पहले यह दोनों आपस में रहने को नहीं तैयार हुए थे जिसको लेकर कई बार पत्नी को अलग-अलग फिर दोनों को एक साथ कई बार काउंसलिंग कराई गई।काफी काउंसलिंग के बाद दोनों पति पत्नी का आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया। जिस पर दोनों पति-पत्नी आपस में प्रेम पूर्वक रहने के लिए खुशी-खुशी तैयार हुए। महिला पुलिस द्वारा किए गए इस सराहनीय कार्य के लिए उन दोनों ने महिला थाना की भूरि भूरि प्रशंसा किया। इस मौके पर महिला थाना में तैनात उपनिरीक्षक संजीव मिश्रा महिला कांस्टेबल अंशु नेहा मिश्रा मौजूद रही।

चार्जिंग के दौरान ई-रिक्शा में लगी आग, गृहस्थी भी जली

उन्नाव, (संवाददाता)। हसनापुर गांव में सोमवार रात चार्जिंग के दौरान ई-रिक्शा में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की लपटें तिरपाल और छप्पर तक पहुंच गई और गृहस्थी के सामान को भी चपेट में ले लिया। आग की सूचना पर गांव पहुंचे लेखपाल ने नुकसान का आकलन किया। कोतवाली क्षेत्र के हसनापुर गांव निवासी सुखदेव मौर्य ई-रिक्शा चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता है। सोमवार रात 11 बजे घर आने के बाद उसने ई-रिक्शा को चार्जिंग के लिए लगाया था। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट होने से ई-रिक्शा में आग लग गई। आग घर में बंधे तिरपाल तक पहुंच गई और फिर छप्पर में लग गई। आसपास के लोगों ने दो घंटे में आग पर काबू पाया। पीड़ित के मुताबिक आग से पांच क्विंटल गेहूं, बिस्तर के साथ 20 हजार रुपये भी जल गए। तहसीलदार अविनाश चौधरी ने बताया कि आग की सूचना पर राजस्व कर्मियों को मौके पर भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

हिलगी टीम ने लउवा टीम को हराकर जीती जीती ट्रॉफी

उन्नाव, (संवाददाता)। हिलौली ब्लॉक के हड़हरा गांव में खेली जा रही क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला मंगलवार को खेला गया। इसमें हिलगी टीम ने लउवा टीम को 11 रन से हराकर चौंपियन बनी और ट्रॉफी पर कब्जा किया। हिलगी टीम के कप्तान अंकित यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। टीम ने निर्धारित 16 ओवर में 113 रन बनाए। टीम की ओर से आजाद ने 26 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी लउवा की टीम 102 रन ही बना सकी। हिलगी ने 11 रन से जीत दर्ज की। हिलगी टीम के गेंदबाज अभिषेक मंडेला ने बेहतरीन गेंदबाजी कर पांच विकेट लिए। उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। वहीं खिलाड़ी आजाद को मैन ऑफ द सीरीज के लिए चुना गया। मुख्य अतिथि अधिवक्ता रजत शुक्ला ने विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान समाजसेवी गंगा सागर यादव, सुनील गोस्वामी, सुरेश साहू, राजकिशोर, संजय गौरव, रामप्रताप यादव, अभिषेक सिंह, सचिन कुशवाहा, तैयब अली आदि मौजूद रहे।

सांस लेने में हुई परेशानी, दो बुजुर्ग व एक महिला की मौत

उन्नाव, (संवाददाता)। सांस लेने में परेशानी होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए दो बुजुर्गों और एक महिला की मौत हो गई। परिजन शव लेकर घर चले गए। डॉक्टरों ने बताया कि तीनों को गंभीर हालत में भर्ती किया गया था। एबीनगर निवासी मोबीनुद्दीन (75) की कई दिन से तबीयत खराब चल रही थी। सोमवार देर रात तबीयत बिगड़ने पर बेटे तसकीम ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं नेवाजगंज के अध्या (75) को भी सांस लेने में परेशानी होने पर मंगलवार को बेटा कमल जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टरों ने उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया जहां उनकी भी मौत हो गई। इसी तरह एबीनगर निवासी अरविंद कुमार की पत्नी निशा (54) की भी तबीयत गंभीर होने पर परिजन जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे लेकिन यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ईएमओ डॉ. दिलीप ने बताया कि महिला को परिजन मृत अवस्था में लेकर आए थे।

तापमान में वृद्धि से सर्दी से मिली राहत, तीन दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम

गोरखपुर, (संवाददाता)। पिछले दो-तीन दिनों में मौसम में हुए बदलाव से राहत मिलने लगी है। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान 20 डिग्री से अधिक रहा। न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई। अनुमान है कि अगले तीन दिनों तक मौसम लगभग ऐसे ही बना रहेगा। मंगलवार को तापमान अधिकतम 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह जल्दी धूप खिलने के कारण दिन में लोगों को बड़ी राहत मिली। हालांकि, सूर्योदय के साथ ही ठंड लगने लगी। मंगलवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच अंतर 15.4 डिग्री सेल्सियस का रहा। अधिकतम तापमान सात जनवरी से ही लगातार बढ़ रहा है।

पंजाबी समाज ने धूमधाम से मनाया लोहड़ी का त्योहार

गोरखपुर, (संवाददाता)। पंजाबी समाज ने मंगलवार के लोहड़ी पर्व धूमधाम से मनाया। गुरुद्वारों से लेकर घरों तक लोहड़ी का उल्लास देखने का मिला। शहर के प्रमुख गुरुद्वारा जटाशंकर, पैडलेगंज और मोहद्दीपुर के साथ ही सभी पंजाबी मंदिर और घरों में अरदास के बाद लोहड़ी जलाकर समाज और परिवार की खुशहाली मांगी गई। लोगों ने पारंपरिक अंदाज में लोहड़ी को मनाया और एक-दूसरे को प्रसाद खिलाकर बधाई दी। गुरुद्वारा जटाशंकर में मनाए जा रहे उत्सव में सत्संग के साथ उल्लास का माहौल दिखा। सभी वर्ग के लोगों ने गुरु के सामने अरदास की फिर लोहड़ी जलाई। लोहड़ी पर्व की शुरुआत गुरुद्वारा जटाशंकर में रात आठ बजे गुरबाणी और अरदास से हुई। सत्संग के बाद कार्यक्रम में आए श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा प्रांगण में आकर लोहड़ी की अरदास की और भजन गाकर लोहड़ी की अग्नि प्रज्वलित की। इस दौरान लोहड़ी की विशेष परंपरा के रूप में मूंगफली, मक्का, गुड़, रेवड़ी, चना और ड्राई-फ्रूट को प्रसाद के रूप में पहले लोहड़ी की अग्नि को समर्पित किया। इसके बाद उस प्रसाद को सभी ने बांटा। गुरुद्वारा के प्रमुख ग्रंथी ज्ञानी राज सिंह ने यहां आने वाले श्रद्धालुओं को लोहड़ी के इतिहास के बारे में जानकारी देकर सर्व मंगल की कामना की। कार्यक्रम का संचालन उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी के सदस्य जगनैन सिंह नीटू व आभार ज्ञापन अध्यक्ष जसपाल सिंह ने किया।

अपना स्कूल में धूमधाम से मनाया गया मकर संक्रांति पर्व

(राजन तिवारी संवाददाता अयोध्या धाम)

अयोध्या। गुरुवार को जयसिंहपुर वार्ड के मलिन बस्ती में वंचित वर्ग के बच्चों के लिए समर्पित निःशुल्क अपना स्कूल में सेवाज्ञ संस्थानम के सहयोग से बच्चों में खिचड़ीध्तहरी का सामूहिक भोज किया गया। कार्यक्रम की शुरूआत भारत माता और विवेकानंद जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके किया गया। सब इंस्पेक्टर रणजीत यादव खाकी वाले गुरूजी द्वारा संचालित अपना स्कूल में उपस्थित सभी बच्चों को सम्मान पूर्वक बैठाकर पत्तल

में परोस कर खिचड़ी भोज करवाया गया। इस अवसर पर सेवाज्ञ संस्थानम की सदस्य पूजा सिंह ने बच्चों को साफ सफाई और शिक्षा के महत्व के बारे में विस्तृत रूप से समझाया। खाकी वाले गुरुजी ने बताया कि इस विशेष अवसर पर अनुज सिंह,अमन गुप्ता,कृष्ण कुमार तिवारी,पूजा सिंह,कवयित्री कात्यायनी उपाध्याय,अमित कुमार मिश्र,आशुतोष मिश्रा,मुख्य आरक्षी संदीप सिंह, विष्णु कुमार समेत अपना स्कूल के सहयोगी ऋषभ शर्मा और विनय कुशवाहा मौजूद सामूहिक भोज में सहयोग प्रदान करने के उपरांत खिचड़ी भोज का आनंद लिए!

संक्षिप्त खबरें

छह नई चौकियों पर प्रभारियों की तैनाती, सीमावर्ती क्षेत्रों पर रखेंगे नजर

भदोही, (संवाददाता)। सीमावर्ती क्षेत्रों में अपराध पर नियंत्रण रखने और लोगों तक पुलिस की पहुंच को आसान बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को एसपी ने छह नई चौकियों का सृजन करने के साथ ही वहां प्रभारियों की तैनाती कर दी। जिले में अब तक 24 पुलिस चौकियां थीं। छह चौकी बढ़ने के बाद अब संख्या 30 हो जाएगी। सबसे अधिक भदोही में छह और औराई में पांच चौकियां हैं। एक चौकी महिला थाने में स्थित परामर्श केंद्र का है। नई पुलिस चौकियां गोपीगंज, सुरियावां और दुर्गागंज थाने के अंतर्गत हैं। वहीं, ये चौकियां स्थानीय स्तर पर गस्त, चेकिंग, संदिग्धों की जांच और छोटे-मोटे विवादों का तत्काल निपटरा भी कर सकेंगी। वहीं, बड़े थानों पर बोझ कम होगा। एसपी ने नए चौकी प्रभारियों को अपराध नियंत्रण, पशु तस्करी पर लगाम, छोटे विवादों का तुरंत निपटारा, वांछितों की गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए हैं। नई चौकियों को विशेष रूप से दूरस्थ इलाकों के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में रखा गया है। इससे पुलिस विवादों का तत्काल निपटारा कर सके। बताया कि अभी कुछ अन्य चौकियां भी खोली जानी है। जिसके लिए जगह की तलाश चल रही है।

वीजा मुक्त व्यापार से जर्मनी-भारत के बीच बढ़ेगा कालीन का कारोबार

भदोही, (संवाददाता)। भारतीयों को जर्मनी में वीजा की जरूरत न होने वाली खबर से कालीन उद्योग में राहत की उम्मीद जगी है। जर्मनी भारतीय कालीनों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। वीजा में मिली छूट के बाद निर्यातकों का जर्मनी से व्यापारिक यात्रा में राहत मिलेगी। इससे कालीन उद्योग की बेहतरी के रास्ते खुलेंगे। भारत और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच गुजरात में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किया। इसमें भारतीयों के लिए जर्मनी में किसी प्रकार के वीजा की जरूरत न होने वाला समझौता भी शामिल है। अमेरिका के बाद भारतीय कालीनों का सबसे बड़ा आयातक जर्मनी है। जर्मनी में वर्ष भर में दो ऐसे टेक्सटाइल एक्सपो होते हैं, जो भारतीय कालीन निर्यातकों में खासा लोकप्रिय हैं। डोमोटेक्स – 2026 और हिमटेक्स्टिल-2026 में भाग लेने के लिए भारत से एक सौ से अधिक कालीन व्यापारी इन दिनों जर्मनी के दौरे पर हैं। जर्मनी से भारत के रिश्ते प्रगाढ़ हैं फिर भी यूरोपीय देशों का दौरा करने के लिए वीजा मिलना आसान नहीं होता। भारतीय व्यापारियों को जब-जब वहां जाने की आवश्यकता हुई है, वीजा के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। अब जर्मनी जाने के लिए अब भारतीयों को वीजा की आवश्यकता खत्म होने के बाद निर्यातकों को राहत मिलेगी। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) के उपाध्यक्ष असलम महबूब ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने जर्मनी को 1053 करोड़ रुपयों के कालीन निर्यात किए थे। अमेरिका के 50 प्रतिशत टैरिफ थोपे जाने के बाद अधिकतर भारतीय कालीन निर्यातक जर्मनी समेत अन्य यूरोपीय देशों को अपनी पहुंच बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिकी टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद भारतीय निर्यातक पहले से जर्मनी में व्यापार बढ़ाने के अवसर तलाश कर रहे थे। दोनों देशों के बीच जो सहमति बनी है, वह स्वागतयोग्य है। इसमें जर्मनी के चांसलर और भारतीय प्रधानमंत्री कीसराहना होनी चाहिए।

नहर पटरी पर 54 किलोमीटर वैकल्पिक मार्ग बनाएगा सिंचाई विभाग

उन्नाव, (संवाददाता)। नहर पटरी पर फैले अतिक्रमण को हटाने और आवागमन को सुलभ बनाने के उद्देश्य से सिंचाई विभाग आठ करोड़ रुपये की लागत से एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कराने जा रहा है। यह 54 किलोमीटर लंबा खड़ंजा मार्ग दो चरणों में पूरा होगा जिससे जिले के तीन विकासखंड क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा। 3.30 मीटर चौड़ा मार्ग बनने से लोगों को आवागमन सहूलियत मिलेगी। जिले में शारदा खंड और आसीवन ब्रांच नाम की दो प्रमुख नहरें हैं जिनसे 32 रजबहे और 210 माइनर निकली हैं। वर्तमान में इन नहरों की पटरियों पर कई स्थानों पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। अतिक्रमण के कारण पानी का प्रवाह बाधित होता है और अधिकारी भी निरीक्षण के लिए पटरी पर आसानी से नहीं जा पाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सिंचाई विभाग ने खड़ंजा मार्ग निर्माण की योजना बनाई है। पहले चरण में 41 किलोमीटर और दूसरे चरण में 13 किलोमीटर खड़ंजा मार्ग का निर्माण कराया जाएगा। कार्य सफीपुर के मुंडा गांव के पास नहर पटरी से शुरू होगा। निर्माण कार्य के लिए लगभग आठ करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। 3.30 मीटर की चौड़ाई वाले इस मार्ग पर चार पहिया वाहन भी आसानी से गुजर सकेंगे जिससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। नहर, रजबहा व माइनरों की हो सकेगी निगरानी पहले चरण में सफीपुर के मुंडा से नवाबगंज के कुसुंभी तक 41 किलोमीटर लंबे खड़ंजा मार्ग का निर्माण होगा। दूसरे चरण में कुसुंभी से असोहा तक 14 किलोमीटर का खड़ंजा बिछाया जाएगा। इससे सफीपुर से असोहा तक की लोगों को आने-जाने में सहूलियत होगी। साथ ही सिंचाई विभाग के अधिकारी भी नहर, रजबहा और माइनरों की निगरानी आसानी से कर सकेंगे। नहर पटरी को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए सफीपुर के मुंडा से असोहा तक खड़ंजा मार्ग के निर्माण में आठ करोड़ रुपये खर्च होंगे। टेंडर प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। यह मार्ग सफीपुर को असोहा से जोड़ेगा। इससे कई गांवों के लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। विभाग को नहरों की देखरेख में आसानी होगी।

दोस्त से मांग कर ले गए थे स्कॉर्पियो, स्पीडोमीटर 120 पर रुका मिला

उन्नाव, (संवाददाता)। लालाखेड़ा गांव के मोड़ पर डंपर और स्कॉर्पियो की भिड़ंत में भाजपा युवा मोर्चा के बिछिया मंडल के पूर्व उपाध्यक्ष हैप्पी चौधरी की मौत के बाद भाजपाइयों ने परिजन से मिलकर सांत्वना दी। हैप्पी अपने साथी रोहित सिंह की स्कॉर्पियो मांग कर ले गए थे। इधर हादसे में घायल छह साथियों का ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। हादसे में क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो का स्पीडोमीटर 120 पर रुका पाया गया है। असोहा थाना के भल्लाफार्म-कालूखेड़ा मार्ग पर लालाखेड़ा गांव के पास हल्का मोड़ होने से सोमवार सुबह तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सामने से आ रहे डंपर में भिड़ गई थी। हादसे में दही थानाक्षेत्र के मुर्तजानगर गांव निवासी भाजपा नेता हैप्पी चौधरी की मौत हो गई थी जबकि छह साथी घायल हो गए थे। हैप्पी प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में साथियों के साथ बाराबंकी जा रहे थे। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद हैप्पी का शव घर पहुंचा। भाजपा नेताओं के साथ ही जिले की प्रभारी व प्रदेश संगठन मंत्री अर्चना मिश्रा, सांसद साक्षी महाराज, जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी, सहकारी बैंक के जिलाध्यक्ष अरुण सिंह, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रवीण मिश्रा, सपा के पूर्व विधायक उदयराज यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजकुमार रावत आदि ने घर पहुंचे और परिजनों को ढाढ़स बंधाया। प्रभारी मंत्री अर्चना मिश्रा ने कहा कि हैप्पी भाजपा के युवा नेता थे। उनकी मौत हम सभी के लिए कष्टदायी है। सांसद साक्षी महाराज ने परिजन को सांत्वना और हर संभव मदद का भरोसा दिया। परिजन ने जाजमऊ स्थित घाट पर शव का अंतिम संस्कार किया। थानाध्यक्ष फूल सिंह ने बताया कि डंपर चालक की तलाश की जा रही है। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।

स्टॉक रजिस्टर अपडेट न मिलने पर दो दुकानों के लाइसेंस निलंबित

उन्नाव, (संवाददाता)। जिला कृषि अधिकारी शशांक कुमार ने मंगलवार को बीघापुर व सुमेरपुर क्षेत्र में संचालित कीटनाशक व बीज दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्टॉक रजिस्टर अपडेट न मिलने पर उन्होंने दो दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। वहीं एक दुकान को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिला कृषि अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों पर स्टॉक बोर्ड, रेट बोर्ड, वितरण व स्टॉक रजिस्टर, कैश मेमो आदि की जांच की। स्टॉक रजिस्टर अपडेट न मिलने पर किसान सेवा केंद्र पिठाईखेड़ा व दीप ट्रेडर्स भधौरा का लाइसेंस निलंबित कर दिया। वहीं शिव बीज भंडार मनिकापुर सुमेरपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्होंने निर्देश दिए कि रजिस्टर अनिवार्य रूप से बनाएं और अपडेट रखें। दुकान बंद न करें। कीटनाशक दवाओं की बिक्री निर्धारित मूल्य पर ही किसानों को करें। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जायद 2025-26 के सीजन में दहलनी एवं तिलहनी फसलों का क्षेत्रफल व उत्पादन बढ़ाने के लिए निशुल्क बीज मिनी किट योजना शुरू की गई है। उर्द, मूंग एवं मूंगफली के उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज की मिनी किट वितरित होनी है। उर्द बीज की 250, मूंग की 40 व मूंगफली की 50 मिनी किट का लक्ष्य आवंटित किया गया है। जो किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत हैं वे ही इस योजना के पात्र होंगे। इच्छुक किसान कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ंहतपकर्तोंद.नच.हवअ.पद पर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। पोर्टल पर पहले आओ पहले पाओ अथवा निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन होने पर ई-लॉटरी के आधार पर चयन किया जाएगा। किसान 15 जनवरी 2026 तक आवेदन करें। आवेदन करने पर मोबाइल नंबर पर एसएमएस प्राप्त होगा। इसके बाद संबंधित विकासखंड के राजकीय कृषि बीज भंडार से खतौनी, आधारकार्ड और पहचान पत्र की छायाप्रति दिखाकर मिनीकिट प्राप्त कर सकेंगे।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 - 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार-पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।